में जिस भूमि पर हरिजनों ने मकान बनाये थे वह उनके नाम में हस्तान्तरित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह समस्या किन किन राज्यों में विद्यमान है और किन किन राज्यों में इस प्रकार की भूमि हरिजनों के नाम से हस्तान्तरित कर दी गई है ;

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली की स्थिति क्या है और दिल्ली प्रशासन ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(घ) क्या इस बारे में भारत सरकार राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मुत्याल राव): (क) और (ख). उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि जिन जमीनों पर हरिजनों ने मकान बना लिए हैं, उन पर कब्जे के अधिकार सामान्यतः स्थाई पट्टे अथवा किरायेदारी के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। कुछ मामलों में हरिजनों को मालिकाना अधिकार हस्तान्तरित करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली में ऐसी कोई फालतू भूमि नहीं है जिसे, यदि उसका अतिक्रमण कर लिया जाए, हरिजनों को हस्तांस्तरित किया जा सकता है।

(घ) नहीं, श्रीमान ; क्यों कि इस विषय को संविधान के अधीन राज्य सूची के अन्तर्गत गिनाया गया है।

Setting up of a Plant for Manufacturing high pressure Gas Cylinders with Hungarian Collaboration

*609. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH:
SHRI Y. A. PRASAD:
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR:
SHRI N. K. SANGHI:
SHRI R. R. SINGH DEO:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to set up a plant in India with the Hungarian collaboration to produce high pressure gas cylinders;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the estimated cost of the proposal?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). It has been decided in principle to set up a plant in the public sector for the manufacture of H.P. Gas Cylinders. The feasibility-*cum*-project report prepared by National Industrial Development Corporation Ltd., New Delhi on this project is under consideration. The source of foreign technical assistance required for this project and also its capital cost will be decided only after a decision on the project report is taken. An offer of technical assistance has been received from Hungary.

Utilization of Imported Steel Sheets by M|s. Standard Drum and Barrel Mfg. Co. and M|s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.

*610. SHRI SITARAM KESRI:
SHRI S. M. BANERJEE:

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state:

(a) the quantities of 24 gauge imported steel sheets sold by the Indian Oil Corporation to M|s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co. and M|s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd., separately;

(b) whether Government have received any report that these two firms have misutilised 24 gauge imported steel sheets purchased by them from the Indian Oil Corporation; and

(c) whether Government propose to make investigations as to how these two firms have utilised the said imported steel sheets?

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA): (a) The Indian Oil

Corporation sold 24 gauge imported steel sheets in quantities as shown below:

(i) Standard Drum and Barrel Manufacturing Company—1300 tonnes.

(ii) M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.—600 tonnes.

(b) and (c). A letter on this subject was received from a private company, and the matter is being looked into.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची को हानि

*611. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बृजभूषण लाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरज भान :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1968 तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का कुल घाटा 25.57 करोड़ रुपये था जिसमें 1967-68 का घाटा 15.57 करोड़ रुपये था ;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे के लिये कौन कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उनके पदनाम क्या है और उन में से प्रत्येक अधिकारी किस सीमा तक उत्तरदायी था ;

(ग) इस मामले में उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) कारपोरेशन की क्षमता के अनुपात में अब तक कितने क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और कितना माल सप्लाई किया जा चुका है; और

(ङ) इस समय क्षमता तथा क्रयादेश पर माल सप्लाई की स्थिति क्या है और भविष्य में कैसी स्थिति की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) 31 मार्च, 1968 तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, का कुल घाटा 26.0674 करोड़ रुपये था जिसमें 1967-68 का घाटा 16.4652 करोड़ रुपये था ।

(ख) इस आकार और प्रकार की प्रायोजनाओं को पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है जिसमें कार्यकुशलता और उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ता है । जिस अवधि में ये घाटे हुए हैं उसमें निर्माण-कार्य चल रहा था उत्पादन आरम्भ हुआ ही था तथा क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी । इस लिए यह घाटा किसी विशेष वजह या अधिकारी के कारण नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह सूचना यथा संभव मात्रा में एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ङ) पक्के क्रयादेशों के आधार पर, स्थिति इस प्रकार है :-

(1) फाउण्ड्री फोर्ज प्लान्ट :

वर्ष	क्षमता	प्राप्त हुये क्रयादेश (टन)	उपलब्ध क्षमता
1969-70	32350	29721	2629
1970-71	48990	15120	33870

वर्ष 1971-72 और इससे आगे के लिए कोई क्रयादेश नहीं है ।